



अखिल भारतीय बसोर "समाज" विकास समिति

राष्ट्रीय कार्यालय : 5/342, खिचड़ीपुर, नई दिल्ली
राष्ट्रीय उप कार्यालय : शेड नं. 212/4, बी-सेक्टर, 100 क्वार्टर्स, पिपलानी, भोपाल (म.प्र.)

मुख्य सचिव का गोपनीय छल
आ.ड.त. 1815
30/3/10

अध्यक्ष एवं संस्थापक
के.डी.राही

09926769250

*

उपाध्यक्ष

भोपाल दास

रामपाल धौसेले

*

महासचिव

व्ही.के.कोन्डेलकर

09826912505

*

सचिव

एन.एस.बमनेले

अशोक सिरवईया

रमेश गोतेले

*

कोषाध्यक्ष

बी.डी.शुक्लवारे

*

संयुक्त सचिव

गोपाल दास सुनमोरिया

लक्ष्मीप्रसाद बमनेरा

केलाश लाल सिरमोलिया

मदनलाल गौरव

*

सलाहकार

प्रेमकुमार

गिरधारीलाल नेता

नाथुराम वर्मा

जागेश्वर प्रसाद मकोरिया

नाथुराम हथेले

*

सदस्य

रामप्रकाश वंशकार

सी.एल.वंशकार

श्रीमती ललिता धौसेले

के.के.भौरे

माखनलाल सुनमोरिया

आर.के.दमदेरिया

सी.एल.जारे

बी.पी.राही

भागीरथ कुन्डले

जयपाल धुमदेरिया

सोनीलाल गोतम

जी.डी.राही

क्रमांक 47/अ-8/2010

प्रति,

माननीय मुख्य सचिव महोदय,

राज्य शासन,

प्रदेश

विषय :- संपूर्ण भारत में निवासरत बसोर जाति एवं उसकी उपजातियों की मांगों/समस्याओं का निराकरण तीन माह में करने बावत । मांग एवं सूचना-पत्र ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक निवेदन है कि संपूर्ण भारत के राज्यों में निवासरत बसोर समाज एवं उसकी उपजातियों की समस्या एवं मांगों के संबंध में अखिल भारतीय बसोर समाज विकास समिति द्वारा भारत सरकार एवं भारत सरकार के अधीन विभागों एवं समस्त राज्य सरकारों को वर्ष 2003 से लगातार अवगत कराते आ रहे हैं। यहां तक कि भारत के राष्ट्रपति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री महोदय एवं अन्य केन्द्रीय मंत्री महोदय व समस्त राज्यों के महामहिम राज्यपाल महोदय माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन के माध्यम से एवं संस्था द्वारा आयोजित कार्यक्रम जैसे अन्न त्यागी महार्षि गुरु गोकुलदास जी महाराज के जन्मोत्सव समारोह/ क्षेत्रीय बसोर समाज महासम्मेलन/राज्य स्तरीय बसोर समाज महा सम्मेलन/ राष्ट्रीय बसोर समाज महा सम्मेलन में पधारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय को ज्ञापन के माध्यम से एवं पत्रकार वार्ता के माध्यम से अवगत कराते चले आ रहे हैं लेकिन आज दिनांक तक भारत सरकार एवं राज्य सरकारों ने बसोर समाज जो कि संपूर्ण भारत में निवासरत है, की आर्थिक, शैक्षणिक, रोजगार, के संबंध में अध्ययन की स्थिति के संबंध में कोई ठोस कदम नहीं उठाये ।

यहां तक कि लोकतंत्र के मंदिर मध्यप्रदेश की विधानसभा बजट सत्र वर्ष 2006 में 26 फरवरी को तत्कालीन वन मंत्री महोदय अपने प्रश्न के उत्तर के जबाब में बसोर समाज की मांगों/समस्याओं के संबंध में संपूर्ण जानकारी झूठी दी जिससे लोकतंत्र के मंदिर का अपमान हुआ।